ए.एस.ई.एस. शिखर सम्मेलन के अवसर पर स्थायी विकास के संबंध में दिया गया प्रधानमंत्री का वक्तव्य

25 अक्तूबर, 2008

हमारे समय की बड़ी चुनौतियों में से एक स्थायी विकास है। परंतु केवल चर्चित शब्द से आगे बढ़कर स्थाई विकास के लिए एक गतिमान रणनीति तैयार करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है।

हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। इस स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक सामूहिक प्रयास किए जाने जरूरी है ताकि समुचित विकास किया जा सके और विशेष रूप से रोजगार अवसर सृजित किए जा सकें। यदि हम इस प्रयोजन में विफल होते हैं, तो हमें हमेशा अस्थिरता और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।

हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली विकास रणनीतियों की आर्थिक लाभांश के उचित, न्यायसंगत और संतुलित वितरण के रूप में परिणति होनी चाहिए। इसके साथ ही, ये पर्यावरण को संरक्षित करने में भी सहायक होनी चाहिए। केवल तभी हम सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

अतः हमें त्वरित विकास और इसकी पर्यावरणीय स्थिरता दोनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए खाद्यान्न और ऊर्जा दोनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता है।

दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने रियो सम्मेलन के पश्चात प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और वित्त पोषण के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है। हमें विकास और एक अनुकूल आई.पी.आर. शासन प्रणाली स्थापित करने और वित्त व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए नवीन व्यवस्थाओं पर विचार करना होगा।

जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण और विकास के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम विकासशील देशों की गरीबी को कायम रखते हुए अथवा उनके औद्योगीकरण की प्रक्रिया को रोक कर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगामी चुनौती इस बात की है कि उन

विकास रणनीतियों को कैसे लागू किया जाए, जो जीवन स्तर को सुधारने, रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल हैं।

अतः जलवायु परिवर्तन पर यून,एन. फ्रेमवर्क के भीतर व्यावहारिक और सारगर्भित समाधान प्राप्त करने के लिए साझा परंतु विशिष्ट जिम्मेदारियों को बातचीत का मूलभूत सिद्धांत माना जाना चाहिए।

क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है। विकसित देशों का उत्सर्जन वर्ष 2000 से 2005 तक वास्तविक रूप से 2.6% तक बढ़ गया है। हमें इस संबंध में अपने यूरोपीय भागीदारों से अधिक सहयोग के लिए अनुरोध करना होगा। विश्व के विकासशील देश इस दिशा में अपने योगदान के लिए कृतसंकल्पित हैं।

मुझे विश्वास है कि अत्यधिक विकसित देशों के साथ विकासशील देशों के प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन की तुलना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकृष्ट कर रही है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि विश्व के प्रत्येक नागरिक का वैश्विक वातावरणीय अंतरिज में बराबर का हक है।

जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कई समस्याओं का मूल है। परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

अतः विश्व को ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के दक्षतापूर्वक उपयोग को बढ़ाने के लिए नए समझौते की आवश्यकता होगी।

शांति के बिना स्थायी विकास नहीं हो सकता है। आंतकवाद, अतिवाद, और असहिष्णुता हमारे सामाजिक साहचर्य के लिए खतरा हैं।

आंतकवाद से निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को निरंतर मजबूत करना होगा। हमें आंतकवाद को बढ़ावा देने वालों, आयोजकों, वित्त पोषण करनेवालों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना होगा।

अंत में, वैश्वीकरण को यदि सफल बनाना है तो इसे न्यायपूर्ण और संपूर्ण मानवता के हित में होना चाहिए। विकास सर्व समावेशी होना चाहिए। इसे आय और धन संबंधी विसंगतियों को कम करने में सहायक होना चाहिए। इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं का दायरा निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। इसके तहत बहुवाद और विविधता को उचित सम्मान मिलना चाहिए।

एशिया महाद्वीप तेजी से प्रगति कर रहा है और यह वस्तुएं, सेवाएं और ज्ञान उपलब्ध कराने की अपार क्षमताएं सिद्ध कर चुका है। यूरोपीय वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। अतः हम एक-दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। हम इस एतिहासिक अवसर पर विद्वानों और संपूरकों की एक बैठक के दौरान उनका मत जानना चाहते हैं ताकि हमारे दो महाद्वीपों और व्यापक स्तर पर संपूर्ण विश्व में स्थिरता और समृद्धि लाई जा सके।

* * * * * *